

[This question paper contains 6 printed pages.]

Your Roll No.

3407

B

LL.B.

III Term

Paper LB-301 : CONSTITUTIONAL LAW-I

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note : Answers may be written *either* in English *or* in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any *Five* questions.

All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. "The Indian Constitution has not accepted the federal principles in absolute rigidity as it is desired for union without unity." Critically examine the above statement in the light of observations made in decided cases by Supreme Court of India.

20

[P. T. O.]

“भारत के संविधान में परिसंघात्मक सिद्धान्तों को आत्यंतिक अनम्यता में स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इसकी इच्छा एकता बिना संघोन्मुख है।” भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित केसों में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त कथन की समीक्षात्मक जाँच कीजिए।

2. “India had adopted Cabinet System of Government. In England, it has been described that term ‘Crown’ represents, the sum total of governmental powers and synonymous with executive.” Discuss critically the power, position and influence of Indian President in the light of provisions of Constitution and various land-mark decisions. 20

“भारत ने मंत्रिमण्डलात्मक प्रणाली की सरकार को अंगीकार किया है। इंग्लैण्ड में, कहा गया है कि वहाँ ‘Crown’ शब्द सरकार की शक्तियों के कुल योग का प्रतिनिधित्व करता है तथा कार्यकारी का समानार्थी होता है।” संविधान के उपबन्धों और विभिन्न युगान्तरकारी विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रपति की शक्ति, स्थिति और प्रभाव का समीक्षात्मक विवेचन कीजिए।

3. (a) The Governor of State promulgated ordinance in 1988, which he re-promulgated several times. Decide the validity of exercise of this power. 10
- (b) What is appellate jurisdiction of Supreme Court in civil, criminal and special leave to appeal. 10

- (a) एक राज्य के राज्यपाल ने 1988 में अध्यादेश प्रख्यापित किया था जिसको उसने कई बार पुनःप्रख्यापित किया। इस शक्ति के प्रयोग की विधिमान्यता का विनिश्चय कीजिए।
- (b) अपील के सम्बन्ध में सिविल, दाण्डिक और विशेष अनुमति में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता क्या है?
4. (a) Discuss the concept of 'Consultation' and 'Collegium' for the appointment of judges of Supreme Court and High Courts. Can the appointment of judge made by collegium be challenged on any ground? 13
- (b) Critically analyse the provision of residuary power of legislation under the Constitution of India. 7
- (a) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु 'परामर्श' और 'अधिशासी मण्डल' की संकल्पना का विवेचन कीजिए। क्या अधिशासी मण्डल द्वारा की गई न्यायाधीश की नियुक्ति को किसी आधार पर आक्षेपित किया जा सकता है?
- (b) भारत के संविधान के अन्तर्गत विधायन की अवशिष्ट शक्ति के उपबन्ध का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए।
5. (a) Explain the principle of 'repugnancy'. Can it apply when two legislations, one enacted by Parliament

and other by a State Legislature, cover a subject in state list? What procedure has to be followed to make a state law valid, even if the same was repugnant to the parliamentary legislation? 13

(b) What do you mean by writ of mandamus and also give distinction between prohibition and certiorari. 7

(a) 'प्रतिकूलता' के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए। क्या यह तब भी लागू हो सकता है जब दो विधान—एक संसद द्वारा अधिनियमित और अन्य राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित—राज्य सूची के विषय को कवर करते हैं? राज्य विधि को विधिमान्य बनाने के लिए किस प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है, चाहे वह संसदीय विधान के प्रतिकूल ही हो?

(b) परमादेश रिट से आपका क्या अभिप्राय है और प्रतिषेध रिट तथा उत्प्रेषण रिट के बीच भेद व्यक्त कीजिए।

6. Discuss the scope of freedom of trade, commerce and intercourse envisaged under the provisions of Constitution of India in the light of decided land-mark judicial pronouncements. 20

विनिश्चित युगान्तरकारी न्यायिक उद्घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत परिकल्पित व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता की परिधि का विवेचन कीजिए।

7. (a) What are the consequences of proclamation of Emergency made under Article 352 ? 10
- (b) What are the principles of interpretation regarding distribution of subject-matter of legislation. 10
- (a) अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत की गई आपात की उद्घोषणा के क्या परिणाम होते हैं?
- (b) विधान की विषयवस्तु के वितरण सम्बन्धी निर्वचन के क्या सिद्धान्त होते हैं?
8. Write short notes on any *two* : 10+10
- (a) What is power of Parliament to cede Indian territory to a Foreign Nation?
- (b) What are guidelines for invocation of Article 356 in the light of *S. R. Bommai Vs. Union of India* AIR 1994 S.C. 1918?
- (c) Parliament's power to legislate with respect to matters contained in the State list and Centre's control over State Legislature.

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (a) भारत के राज्यक्षेत्र को किसी विदेशी राष्ट्र को अध्वर्षित करने हेतु संसद की क्या शक्ति है?
- (b) एस. आर. बोमानी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1918 को ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 356 का अवलम्ब लेने हेतु क्या दिशानिर्देश हैं?
- (c) राज्य सूची में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में विधान बनाने की संसद की शक्ति और राज्य विधानमण्डल पर केन्द्र का नियन्त्रण।